नियुक्ति से पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना एक पूर्व अपेक्षा बना दी गई है । दिल्ली से सरकारी सेवा में ऐसे किसी अवांछनीय तत्वों, जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल हैं, की नियुक्ति ध्यान में नहीं आई है ।

Disciplinary proceedings under Rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965

8268. SHRI RAGHAVJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a disciplinary proceeding initiated under Rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965 can be concluded without affording the accused any opportunity to lead his witnesses and evidence whatsoever; and

(b) if so, details of the relevant provisions and if not, what are the corrective measures available to the awardee of a penalty and what is the methodology thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) Where a penalty has been imposed without giving adequate opportunity to the delinquent Government servant to present evidence through his own witnesses he may prefer an appeal or revision/review petition to the prescribed authority.

Separate lists for substantive appointments and temporary vacancies

8269. SHRI H. HANUMAN THAPPA:

SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Administrative Tribunal in a recent judgement has held that Central Secretariat Service Rules contemplate preparation of two separate select lists, one for the purpose of making substantive appointments to Section Officers Grade and the other for the purposes of filling temporary vacancies in this grade and that the manner of preparation of both these lists is to be laid down in the Fourth Schedule to these Rules;

(b) whether the Schedule requires fixation of a centralised zone for the purposes of making such select lists;

(c) whether substantive appointments in the past have been made without any such centralised zone having been fixed and it has resulted in the inter-cadre anomalies in the substantive appointments of the select list officers; and

(d) whether Government propose to fix centralised zones for the purposes of making substantive appointments of select list officers with a view to remove these anomalies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Sub rule (1) of rule 13 of CSS rules, 1962 deals with appointments against substantive vacancies; and sub rule (2) of the same deals with appointments against temporary vacancies. Sub rule (5) of the same rule provides that "for the purpose of sub-rule (1) and (2), a Select List for Section Officers Grade shall be prepared and may be revised from time to time.' Thus, one Select List is prepared for this purpose. The incumbents of the Select List get appointed substantively on availability of substantive vacancies. From 1989, however, all appointments including appointments in the Select List, are made against regular vacancies. The Central Administrative Tribunal has not changed the above position in its recent judgement in OA Nos. 996/1993, 157/1994, 492/1994 and 629/1994;

(b) to (d) The Fourth Schedule to CSS Rules, 1962 provides that officers

of the Assistants Grade who have rendered not less than eight years' approved service in that Grade and are within the range of seniority can be added in the Select List. The range of seniority for this purpose was fixed for each Select List.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निर्भय होकर सूचनाएं देने की अपील के बाद सामने आये भ्रष्टाचार के मामलों के समाचार

8270. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 1994-95 के दौरान लोगों को निर्भयता से भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में सूचना देने के लिए अपील करने के बाद ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं ;

(ख) 31 अक्तूबर, 1994 तक कितने मामलों का पता लगाया गया और ये मामले किन-किन विभागों से संबंधित थे और उनके निकट विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाई की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को मार्ग-दर्शन और सहायता देने का विचार रखती है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने तथा इसे स्वीकार करने के आरोपों के संबंध में सूचना देने की जनता से अपील करने के बाद अब तक 45 मामले दर्ज किये गये हैं।

(ख) 31 अक्तूबर, 1994 तक ऐसे कुल 25 मामलों का पता लगा। संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की संख्या को विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)** । पूरी जांच करने के पश्चात् 25 में से 18 मामलों को विचारण हेतु भेज दिया गया, 5 को आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही की सिफारिश करते हुए उनके विभागों को भेज दिया, एक मामले में उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश की गई। बचे हुए एक मामले की सभी जांच की जा रही हैं तथा इसका निरोध विधि के अनुसार निपटान किया जाएगा ।

(ग) विधि के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं।

विवरण

विभाग का नाम	मामलों की संख्या
न्यू इण्डिया एशोरेंस कम्पनी	1
कस्टमस	1
दिल्ली विकास प्राधिकरण	3
डेसू	1
एम०टी०एन०एल०	6
दिल्ली पुलिस	4
दिल्ली नगर निगम	2
डाक विभाग	1
गैर-सरकारी व्यक्ति	1
आय कर	2
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	1
दूरदर्शन	1
एन०पी०सी०सी० (राष्ट्रीय परियोजना) निर्माण निगम लिमिटेड	1 –
	–
	25